भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 115
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2024
सोमवार, 31 आषाढ़, 1946 (शक)

स्किल इंडिया डिजिटल और युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार

115. श्री विजय कुमार दूबेः श्री प्रदीप पुरोहितः श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः
श्री बृजमोहन अग्रवालः श्री विजय बघेलः डॉ. जयंत कुमार रायः
श्री गणेश सिंहः श्रीमती स्मिता उदय वाघः श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री बिद्युत बरन महतोः श्री पी. पी. चौधरीः श्री मनोज तिवारीः
डॉ. आलोक कुमार सुमनः श्रीमती कृति देवी देबबर्मनः श्री जुगल किशोरः
श्री विष णु दयाल रामः श्री धर्मबीर सिंहः डॉ. संजय जायसवालः
श्री नव चरण माझीः श्री शंकर लालवानीः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करने तथा नई नौकरियों की आवश यकता को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार स्कील इंडिया डिजिटल पहल के अंतर्गत नए डिजिटल पाठ्यक्रमों की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान राज्य के पाली जिले में कार्यरत केंद्रों का ब्यौरा तथा संख्या क्या है;

(घ) सरकार द्वारा शुरू की गई स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) पहल की मुख्य विशेषताएं क्या है तथा इसके क या उद्देश्य हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा की गई पहल देश में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को अपनाने को बढ़ावा देगी तथा उक्त पहल किस प्रकार उद्योग 4.0 का समर्थन करेगी; और

(च) एसआईडी का उपयोग करके नागरिक को मिलने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस कर भविष्य के लिए तैयार करना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने तथा प्रशिक्षुओं की नियोजनीयता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

i. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत प्रस्तुत प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से विकसित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में उद्योग जगत के अग्रणियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है।

ii. उद्योग 4.0 की आवश्यकता को संबोधित करते हुए भविष्य के लिए तैयार जॉब रोल, ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों को पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्राथमिकता दी गई है। सीटीएस के तहत भी, उभरती प्रौद्योगिकियों में भविष्य की जॉब रोल की मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक युग के पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।

iii. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक के रूप में की गई है, जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियम एवं मानक स्थापित करता है।

iv. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग मांग के अनुसार अर्हताएं विकसित करें और उन्हें श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ मैप करना और उद्योग वैधता प्राप्त करना।

v. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू स्कीम और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को कार्यान्वित कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य आईटीआई छात्रों को औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

vi. राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) से जुड़े पाठ्यक्रमों में कार्यरत प्रशिक्षण (ओजेटी) और रोजगार कौशल के घटक भी होते हैं।

vii. डीजीटी ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क (पूर्ववर्ती क्रेस्ट अलायंस), अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

viii. एनएसडीसी, बाजार आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को सहयोग और संरेखित करते हैं।

ix. एनएपीएस के अंतर्गत, शिक्षुता प्रशिक्षण और शिक्षुता कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ जुड़ाव बढ़ाने को बढ़ावा दिया जाता है।

x. भारत सरकार ने दस देशों अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इजरायल, ताइवान, ऑस्ट्रिया, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और फिनलैंड के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि इन देशों में मांग के अनुरूप कौशल को संरेखित किया जा सके।

xi. भारत सरकार ने विदेशी देशों के लिए कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए 30 कुशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।

(ख) स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) अपने डिजिटल लर्निंग भागीदारों द्वारा प्रदान किए जाने वाले बिग डेटा, मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स आदि पर भावी पाठ्यक्रम प्रदान करके भारतीय कार्यबल को उद्योग 4.0 के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर इंडस्ट्री 4.0 कोर्स जैसे कि विकसित एआई के साथ पायथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन, जेनरेटिव एआई, सुपरवाइज्ड लर्निंग के साथ क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल बनाना, डेटा एनालिटिक्स एसेंशियल, रिलेशनल डेटा वेयरहाउस में एनालिटिक्स डेटा, साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल, डेटा साइंस का परिचय, किसान ड्रोन ऑपरेटर, ईवी सर्विस टेक्नीशियन, बायो-वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही अन्य प्रमाणन पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं।

(ग) राजस्थान के पाली जिले में एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत केंद्रों की संख्या निम्नानुसार है:

स्कीम का नाम	प्रशिक्षण केंद्रों के नाम
पीएमकेवीवाई	9
एनएपीएस	28*
सीटीएस (आईटीआई)	17

*प्रतिष्ठानों की संख्या

(घ से च) स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) सरकार की दो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं - स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया के बीच का संबंध है। यह एक मोबाइल-फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत के कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता परिदृश्य को समन्वित करने के लिए तैयार किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कौशल की पहुँच का विस्तार करना और देश के युवाओं को केवल भौतिक प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे पर निर्भर किए बिना डिजिटल रूप से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन को अवसर प्रदान करना है। यह कौशल संवर्धन के लिए एक व्यापक और सुलभ मंच प्रदान करता है, उद्योग-संबंधित कौशल पाठ्यक्रम, शिक्षुता और जॉब के अवसर और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करता है। एसआईडीएच कौशल अवसरों का एक डिजिटल विस्तार और एकीकृत मंच है जिसमें हितधारकों के बीच डिजिटल जॉब एक्सचेंज है। एसआईडीएच प्लेटफ़ॉर्म और इसका मोबाइल एप्लिकेशन सितंबर, 2023 को शुरू किया गया था।

कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता परिदृश्य के लिए एसआईडीएच भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में से एक है। यह एक नागरिक-केंद्रित मंच है जो प्रत्येक नागरिक को अपने ज्ञान और रुचियों से जुड़े कौशल पाठ्यक्रमों का चयन करने और सीखने का अधिकार देता है। यह शिक्षा और कैरियर लक्ष्यों के साथ जुड़े कौशल पाठ्यक्रमों का चयन करने में मदद करता है। स्किल इंडिया डिजिटल ऑनलाइन और कक्षा-आधारित दोनों तरह के कौशल पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

एसआईडीएच को कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता परिदृश्य के लिए भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के सिद्धांतों पर तैयार किया गया है। एसआईडीएच डिजिटल कौशल के लिए शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, पोर्टेबल सत्यापित क्रेडेंशियल्स और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए बहुभाषी विकल्प आदि के माध्यम से नागरिकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए कौशल कार्यक्रम के संकेन्द्रण को भी सक्षम बनाता है, जिससे प्रत्येक नागरिक को अपनी रूचि के अनुसार कई कौशल कार्यक्रमों में से चयन करने का अधिकार मिलता है।

*****